माननीय न्यायमूर्ति आर.सी. कथुरिया के समक्ष

टेलस्ट्रा विशेष संचार प्राइवेट लि. — याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य व अन्य— *उत्तरदाता*

Crl.M. स. - 26225 /एम, सन् 2002

20 दिसंबर, 2002

भारतीय दंड संहिता, 1860 — धारा 406, 420 और 120-बी के साथ धारा 34 — धोखाधड़ी और साजिश के आरोप पर प्राइवेट लिमिटेड. कंपनी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने वाली पब्लिक लि. कंपनी।— सी.जे.एम. ने सम्मन आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं को मुकदमे का सामना करने का निर्देश दिया— रद्द करना — उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही कोप् प्रारंभिक चरण पर रद्द करने का अधिकार — उसका उपयोग- केवल ऐसे मामलों में जहां शिकायत / एफआईआर में लगाए गए आरोप यदि उनके अंकित मूल्य पर लिए जाएँ और स्वीकार किए जाएँ तो संपूर्णता अपराध के आयोग का खुलासा नहीं करती है — आरोपी द्वारा समझौते के नियमों और शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं - ग़लतफ़हमी और धोखाधड़ी के आरोप न तो रिकॉर्ड का समर्थन करते हैं और न ही प्रथम दृष्टया से आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और बेईमानी का मामला बनता है — मुद्दा पूरी तरह दीवानी है - आपराधिक न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है ---- आपराधिक शिकायत और सम्मन आदेश रद्द होने के योग्य हैं।

यह निर्णय लिया गया कि नागरिक और आपराधिक कार्यवाही की प्रकृति और दायरा तथा मामलों में आवश्यक प्रमाण का मानक अलग और अलग है जिसे उस चरण में भी ध्यान में रखा जाना चाहिए जहाँ एफआईआर और समन आदेश को रद्द करने कि प्रार्थना की जाती है- हालांकि न्यायालय की शक्ति को निहित असाधारण रूप से और दुर्लभ मामलों में ही प्रयोग किया जाना है - उसी समय, न्यायालय आपराधिक कार्यवाही की अनुमति नहीं देगा जहां ऐसे तथ्यों का खुलासा किया गया है, इस तरह की आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा - जहां मामला अनिवार्य रूप से नागरिक प्रकृति का है, लेकिन आपराधिक अपराध का एक लबादा दिया गया है, न्यायालय शिकायतकर्ता को आपराधिक

न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं देगा, चूंकि आपराधिक कार्यवाही, उपलब्ध अन्य क़ानूनी उपायों का छोटा रास्ता नहीं है - यह इस कारण से है क्योंकि किसी व्यक्ति का अभियोजन गंभीर मामला है, इसलिए न्यायालय ने इस पर जोर दिया है एक प्रक्रिया जारी करने से पहले इसे बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।

(पैरा 20)

आगे अभिनिर्धारित किया गया, कि प्रथम दृष्टया से ये नहीं है कि आरोपी ने शिकायतकर्ताओं को शिकायतकर्ताओं के साथ समझौतों में प्रवेश करने हेतु बेईमानी और धोकेबाज़ी के साथ प्रेरित किया था - यह स्पष्ट है रिकॉर्ड पर लाये गए नागरिक विवाद को शिकायतकर्ताओं द्वारा आपराधिकता का रंग देने की मांग की गई है ताकि उन पर धारा 406, 420 और 120-बी के साथ धारा 34 आईपीसी का मुकदमा चलाया जा सके - मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित शिकायत और सम्मन आदेश दाखिल करना रिकॉर्ड के हिसाब से ही न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है.

(पैरा 29)

आर.एस. चीमा, सीनियर. अधिवक्ता के साथ आर.एस. राय, गौतम दत्त और राजिंद्रा बरोट, याचिकाकर्ताओं के लिए एडवोकेट

संजीव शियोखंड, सह-सरकारी वकील, हरियाणा राज्य कि लिये

अश्वानी कुमार, सीनियर. वकील, विकास बी और दीपक धिंगरा के साथ, प्रतिवादी 2 और 3 के लिए वकील.

आर. सी. कैथुरिया, न्यायमूर्ति

(1) यह निर्णय उपर्युक्त छह याचिकाओं का निपटान करेगा जिसमें याचिकाकर्ता 2001 की शिकायत संख्या 69 को खारिज करना चाहते हैं दिनांक 1 फरवरी, 2001 (अनुलग्नक-पी। 1) और सम्मन आदेश दिनांक 22 मई, 2001 (अनुलग्नक-पी)। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुड़गांव ने याचिकाकर्ता-अभियुक्तों को धारा 406, 420 और 120-बी के साथ धारा 34, भारतीय दंड सहित, के मुकदमे का सामना करने का निर्देश दिया।

2) इन याचिकाओं में शामिल विवाद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन तथ्यों पर विस्तार से ध्यान देने की आवश्यकता है जिनके कारण याचिकाकर्ता-अभियुक्तों के खिलाफ वर्तमान शिकायत दर्ज की गई। आरपीजी टेलीफोन्स लिमिटेड, शिकायतकर्ता नंबर 1 और आरपीजी सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिमिटेड, शिकायतकर्ता नंबर 2, इन याचिकाओं में प्रतिवादी नंबर 2 और 3 के रूप में सूचीबद्ध हैं, कंपनी अधिनियम, 1956 (इसके बाद 'द' के रूप में संदर्भित) के तहत निगमित और पंजीकृत सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां हैं। अधिनियम') और दिल्ली में स्थित हैं और अधिकृत प्रतिनिधि बी.बी. कौल के माध्यम से उनके द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई शिकायत के शीर्षक में उल्लिखित स्थान पर उनका पंजीकृत कार्यालय है। इन याचिकाओं में हरियाणा राज्य को प्रतिवादी नंबर 1 टेल्स्ट्रा विशेष कम्युनिकेशन लिमिटेड (इसके बाद "टीवीसीएल) के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसमें टेल्स्ट्रा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, आरोपी नंबर 4 (इसके बाद "टेल्स्ट्रा" के रूप में संदर्भित) एक लिमिटेड कंपनी है। ऑस्ट्रेलिया के कानूनों के तहत पंजीकृत (और टेल्स्ट्रा कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के पास 47.1% शेयर हैं, विदेश संचार निगम लिमिटेड के पास 33.3% शेयर हैं और शेष 19.6% इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के पास हैं। बाद के दो शेयरधारक कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनियां हैं। अधिनियम के तहत निगमित और पंजीकृत कंपनी को आरोपी नंबर 1 के रूप में रखा गया है, जबकि अबू डब्ल्यू.एम. शफक़त, आरोपी नंबर 2, पुष्पेंद्र एस मांकड़, आरोपी नंबर 3 शिकायत किए गए अपराध के समय कंपनी की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं। डेरिल स्मिथ, आरोपी नंबर 5 और सिग सोविक, आरोपी नंबर 6 को टेल्स्ट्रा कॉरपोरेशन लिमिटेड, आरोपी नंबर 4, अधिनियम के तहत पंजीकृत एक लिमिटेड कंपनी के निदेशक/प्रधान अधिकारी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो जिम्मेदार थे। अपराध के घटित होने के समय उक्त कंपनी के दैनिक कामकाज के लिए। शिकायतकर्ता के मामले के अनुसार, उपरोक्त नामित आरोपियों ने धोखाधड़ी और साजिश के अपराधों के संबंध में प्रमुख और सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिसने आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 4 के लिए अवैध लाभ की सुविधा प्रदान की थी और इसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता को नुकसान हुआ था।

(3) शिकायतकर्ताओं द्वारा स्थापित मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता नंबर 1 कंपनी के पास शिकायतकर्ता नंबर 2 कंपनी के 100% जारी किए गए शेयर हैं और वह उक्त शेयरों का लाभकारी मालिक है। इस प्रकार, शिकायतकर्ता नंबर 1 शिकायतकर्ता नंबर 1 की होल्डिंग

कंपनी है। शिकायतकर्ता नंबर 2 संचार मंत्रालय, संचार भवन, न्यू के तहत दूरसंचार विभाग द्वारा जारी वैध लाइसेंस के तहत भारत में वीएसएटी सेवाओं के प्रदाताओं में से एक है। दिल्ली सक्षम प्राधिकारी होने के नाते, सितंबर/अक्टूबर 1998 के महीने में, आरोपी नंबर 1 और 4 ने आरोपी नंबर 5 के माध्यम से, जिसने खुद को दोनों आरोपी नंबर 1 और 4 का अधिकृत अधिकारी होने का प्रतिनिधित्व किया, प्रस्ताव के साथ शिकायतकर्ताओं से संपर्क किया। वे पार्टियों के बीच सहमति के अनुसार नियमों और शर्तों पर शिकायतकर्ता नंबर 1 द्वारा रखे गए शिकायतकर्ता नंबर 2 के इक्विटी शेयर खरीदने में रुचि रखते थे। प्रारंभिक बातचीत के बाद, 2 दिसंबर, 1998 को उनके प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई। उस दिन, पार्टियों के बीच समझौते के बिंदुओं को लिखित रूप में लिख दिया गया, जिसकी प्रतिलिपि अनुलग्नक-पी.4 है। आरोपी नंबर 5 द्वारा निष्पादित समझौते के बिंदुओं की शर्तों के अनुसार, आरोपी नंबर 1 और 4 के माध्यम से और उसकी ओर से कार्य करते हुए, आरोपी शिकायतकर्ता नंबर 2 की जारी शेयर पूंजी का 100% खरीदने और अधिग्रहण करने के लिए सहमत हुआ था। नंबर 1. शेयरों की कीमत, होने पर सहमत आरोपी द्वारा अधिग्रहण, रुपये पर तय किया गया था। 7.40 प्रति शेयर. पार्टियों द्वारा तय की गई समय सीमा के अनुसार, टर्म शीट पर हस्ताक्षर 20 दिनों के भीतर पूरा किया जाना था, उचित परिश्रम 50 दिनों के भीतर पूरा किया जाना था और समझौते को 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाना था। इस प्रकार पक्षों के बीच कुल 115 दिन की अवधि निर्धारित की गई। समूह के ऋणों का पुनर्भुगतान 1 जुलाई, 1999 से छह त्रैमासिक किश्तों में किया जाना था, जिसे टेल्स्ट्रा वी-कॉम, आरोपी नंबर 1 द्वारा शेयर धारकों के समर्थन से सुरक्षित किया जाना था। गारंटी टेल्स्ट्रा वी-कॉम द्वारा ली जानी थी। 30 अप्रैल, 1999 तक। पार्टियों के बीच इस बात पर भी सहमति हुई कि टर्म शीट टेल्स्ट्रा वी-कॉम पर हस्ताक्षर करने के 15 दिनों के भीतर। उन्हें यह बताना था कि वे कितने लोगों को अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं। फिर आरपीजी सैटकॉम को नियुक्ति की शर्तों के अनुसार कर्मचारियों को नोटिस देकर और अलग होने पर तीन महीने के वेतन तक मुआवजा देकर जनशक्ति को कम करने की प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता थी। लियन एस्क्रो खाता खोलने वाले बैंक को ट्रस्टी के रूप में कार्य करना था। अधिग्रहण मूल्य का 25% भुगतान टर्म शीट पर हस्ताक्षर करने के सात दिनों के भीतर नो लियन एस्क्रो खाते में जमा किया जाना था। एस्क्रो ए/सी पर अर्जित ब्याज को टेल्स्ट्रा वी-कॉम में जमा किया जाना था। इस बात का भी ध्यान रखा गया कि उचित परिश्रम कैसे किया जाए और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के संबंध में भी। टेल्स्ट्रा वी-कॉम के नामांकित व्यक्ति को आरपीजी स्टेट कॉम की बोर्ड बैठकों में आमंत्रित किया जाना आवश्यक था। टर्म एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद।

शिकायतकर्ता ने शिकायत में आगे कहा कि दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिए गए लाइसेंस के संदर्भ में, वे किसी भी तरीके से किसी अन्य निकाय को ट्रांसपोंडर के उपयोग का उप-लाइसेंस नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आरोपी उक्त ट्रांसपोंडर पर शिकायतकर्ता के लाइसेंसिंग अधिकारों का पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए शिकायतकर्ता के शेयरों के अधिग्रहण के इच्छुक थे क्योंकि उक्त ट्रांसपोंडर के उपयोग की सुविधा शिकायतकर्ताओं सहित चुनिंदा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के पास उपलब्ध थी। शिकायतकर्ता के अनुसार समझौते की उपर्युक्त शर्तें शिकायतकर्ता की ट्रांसपोंडर/नेटवर्क सेवा और उससे जुड़ी अन्य सुविधाओं का उपयोग करने और शिकायतकर्ता को धोखा देने के एकमात्र उद्देश्य और इरादे से आपराधिक साजिश द्वारा उन्हें धोखा देने की आरोपी की साजिश थी। ताकि वे अपने दायित्व से पीछे हट जाएं। समझौते के बिंदुओं के निष्पादन के समय अभियुक्तों को पूरी तरह से पता था कि ट्रांसपोंडर स्पेस एक दुर्लभ वस्तु थी और मुफ्त में उपलब्ध नहीं थी और वे ऐसे ट्रांसपोंडर स्पेस वाली कंपनी का अधिग्रहण किए बिना उक्त सुविधा का आनंद नहीं ले सकते थे। इसलिए, उन्होंने शिकायतकर्ताओं को गलत जानकारी देने की साजिश रची कि वे शिकायतकर्ता नंबर 2 की इक्विटी पूंजी खरीदेंगे और हासिल करेंगे, जिसके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध लाइसेंस था। शिकायतकर्ताओं के मामले के अनुसार अधिग्रहण की दलील को आरोपियों ने नेटवर्क सुविधाओं और शिकायतकर्ताओं की मार्केटिंग ताकत हासिल करने के लिए एक मार्ग और कार्यप्रणाली के रूप में लिया था ताकि शिकायतकर्ताओं का व्यवसाय हासिल किया जा सके और अपने स्वयं के व्यवसाय को मजबूत किया जा सके। इसका उद्देश्य शिकायतकर्ता नंबर 2 की क्षमता को कम करके और उसके ग्राहकों को प्राप्त करके उसके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाना है।

(4) उपरोक्त बिन्दुओं के क्रियान्वयन के तुरंत बाद, शिकायतकर्ता अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए परिणामस्वरूप उत्पन्न धारा 6 ने आरोपियों को अपने कर्मचारियों, तकनीशियनों और अन्य कर्मियों तक उन सभी सूचनाओं तक पहुंच की अनुमति दी जो मई 1999 में ट्रांसपोंडर स्पेस के उपयोग सहित प्रकृति में संवेदनशील थीं। गोपनीय जानकारी, रिकॉर्ड और अन्य सामग्री प्राप्त करने के बाद, आरोपियों ने धोखाधड़ी करने के लिए शिकायतकर्ताओं और उनके द्वारा रची गई साजिश को आगे बढ़ाने में उपरोक्त समझौते के संदर्भ में अपने दायित्वों को पूरा करने में देरी हुई और 115 दिनों की अवधि के भीतर आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहे। बल्कि, आरोपी नंबर 1 और 2 शिकायतकर्ताओं

का प्रतिनिधित्व करते रहे और उन्हें विश्वास दिलाते रहे कि वे एक इकाई बन गए हैं। नवंबर 1999 के महीने में, शिकायतकर्ताओं को दूरसंचार विभाग को कुछ लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना पड़ा और इसी कारण से उन्होंने भुगतान की व्यवस्था करने के लिए आरोपी नंबर 1 से संपर्क किया। आरोपी ने तदनुसार शिकायतकर्ताओं की ओर से शुल्क का भुगतान किया। आरोपी ने शिकायतकर्ताओं से समझौता ज्ञापन (संक्षेप में 'एमओयू) (अनुलग्नक-पी. 5) पर हस्ताक्षर करने के लिए भी संपर्क किया, जिसे 15 नवंबर, 1999 को पार्टियों के बीच निष्पादित किया गया था। शिकायतकर्ताओं के संस्करण के अनुसार, उक्त एमओयू में विवरण शामिल था अधिग्रहण की शर्तें-पत्र जैसा कि 2 दिसंबर, 1988 के समझौते के बिंदुओं में संदर्भित किया गया था। इस तरह की शर्तों का उद्देश्य अभियुक्त की कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता नंबर 2 के हस्तांतरण और अधिग्रहण के विशिष्ट तौर-तरीकों को प्रदान करना था। उसी दिन आरोपी ने शिकायतकर्ताओं से नेटवर्क सेवा अनुबंध (अनुबंध-पी. 6.) पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए भी कहा। नेटवर्क सेवा समझौते के अनुसार, आरोपी नंबर 1 को अधिग्रहण पूरा होने से पहले शिकायतकर्ता से कुछ नेटवर्क सेवाएं प्राप्त करने की सुविधा दी गई थी। नेटवर्क सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करते समय, आरोपियों ने शिकायतकर्ताओं को आश्वासन दिया था कि वे हस्ताक्षरित और निष्पादित समझौते की प्रत्येक शर्तों का पालन करेंगे और जल्द ही शिकायतकर्ता नंबर 2 और 1 एक इकाई बन जाएंगे। इस प्रतिनिधित्व पर विश्वास करते हुए, शिकायतकर्ताओं ने आरोपियों को अपने उपकरणों, सुविधाओं का उपयोग करने और कंपनी और उसके मामलों तक पहुंच की अनुमति दी। बताया जाता है कि आरोपियों ने शिकायतकर्ताओं को किसी अन्य पक्ष के साथ बातचीत करने से रोकने के लिए एमओयू में विशेष खंड का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा एमओयू में आरोपियों को शिकायतकर्ताओं के केवल उन चुनिंदा कर्मचारियों को बनाए रखने का प्रावधान था जिन्हें वे अधिग्रहण के बाद नियोजित करना चाहते थे। इसके अलावा एमओयू के तहत आरोपी ने शिकायतकर्ताओं की बोर्ड बैठकों में भाग लेने और इसकी संप्रभु गतिविधियों की निगरानी करने जैसे विशेषाधिकार प्राप्त किए जो सुविधा प्रदान करते हैं, उन्हें खरीदने के आश्वासन के अलावा नहीं बढ़ाया गया होता और शिकायतकर्ताओं का हिस्सा प्राप्त करें। आरोपी नंबर 1 को 31 जनवरी, 2000 तक उचित परिश्रम पूरा करना था और पार्टियों के बीच सहमति के अनुसार शेयरों के अधिग्रहण के लिए लेनदेन 28 फरवरी, 2000 को बंद होना था। इसके अलावा नेटवर्क सेवा समझौते के संदर्भ में, शिकायतकर्ता नंबर 2 को रुपये के मामूली शुल्क पर नेटवर्क सेवा प्रदान करनी थी। 0.585 मिलियन और पी. 078 मिलियन प्रति माह, जिसकी राशि लेनदेन के वास्तव में पूरा होने तक

पार्टियों के बीच एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में तय की गई थी, जैसा कि 15 नवंबर के समझौते के खंड 2.1, 3.1, 4.1, 4ए.2, 6.3, 6.4 में स्पष्ट रूप से बताया गया है। 1999. खंड 4ए के संदर्भ में, डीओटी को भुगतान का एक हिस्सा अधिग्रहण मूल्य के लिए नई जमा राशि के लिए प्रदान किया गया था। शिकायतकर्ता नंबर 2 को उन कर्मचारियों को बनाए रखने की आवश्यकता थी जिन्हें आरोपी समझौते के खंड 7.1 के संदर्भ में बनाए रखना चाहता था। शिकायतकर्ता को समझौते के खंड 9.1 के संदर्भ में आरोपी कंपनी के अलावा किसी तीसरे पक्ष से जुड़े बातचीत के किसी अन्य प्रस्ताव या किसी अन्य कार्य को छोड़ने की भी आवश्यकता थी। संविदात्मक दायित्व के अनुसार, शिकायतकर्ता कंपनी के संरचनात्मक, पुनर्गठन, विविधीकरण, अधिग्रहण, नए निवेश, बिक्री या समामेलन नहीं कर सकते थे। शिकायतकर्ताओं के दावे के अनुसार समझौते के इन खंडों ने कंपनी के सुचारू कामकाज में बड़ी बाधाएं पैदा कीं, जिसकी तथ्य आरोपी को पूरी तरह से पता था।

(5) शिकायतकर्ता का आगे का मामला यह है कि आरोपी नंबर 1 को दिए गए अवसरों और विस्तार के बावजूद, वह 31 जनवरी, 2000 तक उचित परिश्रम पूरा करने में विफल रहा। आरोपी के अनुरोध पर इस संबंध में समय को मार्च तक बढ़ा दिया गया था। , 2000 शिकायतकर्ताओं द्वारा सद्भावनापूर्वक। आरोपी नंबर 3 ने 17 दिसंबर, 1999 और 27 मार्च, 2000 को अन्य आरोपियों का प्रतिनिधित्व करते हुए बोर्ड बैठक में भाग लिया। किसी भी स्तर पर अभियुक्त ने समझौते की शर्तों के संबंध में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की थी। मार्च 2000 में शिकायतकर्ता क्रमांक 2 को डी.ओ.टी. का भुगतान करना पड़ा। शुल्क की राशि रु. 140.13 लाख और तदनुसार आरोपी को उक्त भुगतान की व्यवस्था करने के लिए कहा। चूँकि संपूर्ण सेवाओं का उपयोग और लाभ अभियुक्तों द्वारा किया जा रहा था, इसलिए उन्हें उक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा गया था। अभियुक्तों ने ऐसे आरोपों का भुगतान करने के बजाय यह रुख अपनाया कि बोर्ड के औपचारिक निर्णय तक, उनके लिए उक्त राशि का भुगतान करना संभव नहीं था। अप्रैल, 2000 में एक और शिकायतकर्ताओं द्वारा आरोपियों को संचार संबोधित किया गया था उनसे लेन-देन की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहा जा रहा है लेकिन आरोपियों ने शिकायतकर्ताओं से आग्रह किया कि वे तब तक सेवाएं देना जारी रखें जब तक मासिक सेवा शुल्क रुपये के भुगतान के विरुद्ध पूरी तरह से समायोजित नहीं हो जाता। आरोपी नंबर 1 द्वारा 1,22,59,603 रुपये का भुगतान किया गया। उनके द्वारा यह भी प्रतिनिधित्व किया गया कि वे 24 अप्रैल, 2000 को औपचारिक मंजूरी देंगे। उन्होंने शिकायतकर्ताओं को यह भी आश्वासन

दिया कि शिकायतकर्ता नंबर 1 की शेयर होल्डिंग खरीदने और हासिल करने के लिए आवश्यक लेनदेन होगा। 2 पार्टियों के बीच निष्पादित दस्तावेजों में सहमत शर्तों पर किया जाएगा। शिकायतकर्ताओं द्वारा आगे कहा गया है कि रुपये के नाममात्र मासिक सेवा शुल्क को छोड़कर। 0.585 मिलियन और रु. 0.078 मिलियन प्रति माह, नेटवर्क सेवा समझौते में दिए गए प्रावधानों के अनुसार शिकायतकर्ताओं की ओर से आरोपी द्वारा डीओटी को भुगतान की गई राशि को समायोजित करने पर सहमति हुई, पार्टियों के बीच सहमति के अनुसार सुविधाओं के शुल्क के लिए आरोपी द्वारा कोई राशि नहीं दी गई। . आरोपियों को पूरी तरह से पता था कि नेटवर्क सेवा और सुविधाओं की वास्तविक लागत बहुत अधिक होगी और नाममात्र सेवा शुल्क का उद्देश्य इसे कवर करना नहीं था। शिकायतकर्ताओं ने अभियुक्तों को उक्त सुविधाएँ/सेवाएँ प्रदान करना जारी रखा और अभियुक्तों को सभी गोपनीय जानकारी भी प्रदान की क्योंकि उनके द्वारा दिया गया आश्वासन था कि वे शिकायतकर्ता के 100% शेयर हासिल कर लेंगे। समझौते की शर्तों का सम्मान करने के लिए आरोपी की ओर से की गई देरी से शिकायतकर्ता के व्यवसाय और उसके कर्मचारी के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस दिशा में अभियुक्तों की ओर से लंबी देरी से परेशान होकर, शिकायतकर्ताओं ने जुलाई 2000 में तथ्यात्मक स्थिति की पुष्टि के लिए अभियुक्त संख्या 5 को एक पत्र भेजा। शिकायतकर्ता नंबर 2 को गहरा सदमा और अविश्वास हुआ, आरोपी नंबर 1 की ओर से आरोपी नंबर 5 ने शिकायतकर्ताओं को सूचित किया कि उन्हें आरोपी नंबर 1 के बोर्ड के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए समय की आवश्यकता है। अगस्त, 2000 में, शिकायतकर्ता ने आरोपी नंबर 1 को उनके द्वारा ली गई सुविधाओं की लागत का भुगतान करने के लिए कहा गया। जिस अवधि के दौरान आरोपी नंबर 1 ट्रांसपोंडर सुविधा का उपयोग कर रहा था, उस अवधि के लिए ट्रांसपोंडर शुल्क और लाइसेंस शुल्क के लिए 2,43,53,446 रुपये दिए गए। जवाब में, शिकायतकर्ता के रुख के अनुसार, आरोपी नंबर 1 ने यह दलील देकर एक बेतुका रुख अपनाया कि शिकायतकर्ताओं द्वारा दी गई सुविधाओं के लिए लागत और शुल्क की मांग अकेले शिकायतकर्ताओं द्वारा वहन की जानी थी और आरोपी नंबर। 1 रुपये की राशि तक ट्रांसपोंडर स्थान का उपयोग करना चाहेगा। 34 का शिकायतकर्ताओं की ओर से डीओटी को 1,22,59,603 रुपये का भुगतान किया गया था रुपये के मासिक सेवा शुल्क से पूरी तरह से मुक्त। 0.585 मिलियन शिकायतकर्ता ने आरोपियों को उनके दायित्व और आरोप की याद दिलाई आगे उन्हें आश्वासन दिया कि अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी की जाएगी। इस दिशा में कोई प्रगति नहीं होने और अधिग्रहण को प्रभावित करने में अभियुक्तों द्वारा अपनाए गए रुख को देखते हुए, शिकायतकर्ताओं ने 18 अक्टूबर, 2000 को अभियुक्त संख्या

5 को संचार संबोधित किया और अधिग्रहण के तौर-तरीकों को पूरा करने में उनके कारण हुई देरी के बारे में बताया और जवाब दिया। आरोपी ने शिकायतकर्ताओं को सूचित किया था कि आरोपी का निदेशक मंडल है। नंबर 1 वर्तमान में शिकायतकर्ता नंबर 2 के शेयरों की बिक्री और अधिग्रहण के लेनदेन के साथ आगे बढ़ने का इरादा नहीं रखता था। आरोपी के इस संचार ने शिकायतकर्ता को पूरी तरह से चौंका दिया और शिकायतकर्ता पर आरोपी द्वारा की गई धोखाधड़ी और धोखे को स्पष्ट रूप से सामने ला दिया। इसके तुरंत बाद, शिकायतकर्ता नंबर 2 और 1 के अधिवक्ताओं ने क्रमशः 14 नवंबर, 2000 और 16 नवंबर, 2000 को दो अलग-अलग नोटिस आरोपियों को भेजे और उनसे विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से किए गए प्रतिनिधित्व और आश्वासन के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा। , बैठकें चर्चाएँ और बातचीत। अभियुक्त संख्या 1 और 4 ने शिकायतकर्ताओं के अधिवक्ताओं के संचार का अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 12 दिसंबर, 2000, 3 जनवरी, 2001 और 21 दिसंबर, 2000 के पत्रों के माध्यम से जवाब दिया, जो स्पष्ट रूप से अभियुक्तों के अपने से बाहर निकलने के इरादे को बताता है। प्रतिबद्धता। उन्होंने यह रुख अपनाया था कि नेटवर्क सेवा समझौते वाले उनके द्वारा निष्पादित दस्तावेज़ उन पर बाध्यकारी नहीं हैं। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, ऊपर बताई गई परिस्थितियों में, स्पष्ट रूप से विश्वास का जादू, गंभीर विश्वासघात, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और कपटपूर्ण गलत बयानी का अपराध हुआ, जिसके परिणामस्वरूप रुपये का भारी नुकसान हुआ। शिकायतकर्ताओं को 29.22 करोड़ रुपये दिए गए और आरोपियों ने धारा 415, 420, 406 और धारा 120-बी और धारा 415, 420, 406 सहपठित धारा 34 आईपीसी के तहत अपराध किया था। शिकायतकर्ताओं ने प्रार्थना की कि आरोपियों को इन अपराधों के संबंध में बुलाया जाए और दंडित किया जाए।

(6) शिकायत में लगाए गए आरोपों के समर्थन में, बी.बी. कौल (पीडब्लू-1), जो शिकायतकर्ता नंबर 1 के महाप्रबंधक और साथ ही दोनों शिकायतकर्ताओं के अधिकृत प्रतिनिधि हैं, ने अपने बयान के दौरान परिस्थितियों के बारे में बताया। शिकायत में विस्तार से बताया गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि शिकायतकर्ता आरपीजी टेलीफोन लिमिटेड शिकायतकर्ता नंबर 2-आरपीजी सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिमिटेड की कंपनी का मालिक है, जिसके पास 100% जारी शेयर हैं। बाद वाला। उनके अनुसार, शिकायतकर्ता नंबर 2 प्रदाताओं में से एक है भारत में वीसैट सेवाओं के लिए विभाग से वैध लाइसेंस धारक दूरसंचार के जो सक्षम प्राधिकारी है। उनके बयान के अनुसार, आरोपी नंबर 2 अबू डब्ल्यू.एम. शफ़क़त और आरोपी नंबर 3 पुष्पेंद्र एस

मांकड़ ने खुद को आरोपी नंबर 1 के निदेशक/प्रधान अधिकारी होने का प्रतिनिधित्व किया, जिनके पास उसकी ओर से लेनदेन में प्रवेश करने का अधिकार था। इसी तरह, आरोपी नंबर 5 डेरिल स्मिथ और आरोपी नंबर 6 सिग सोविक ने खुद को आरोपी नंबर 4 टेल्स्ट्रा कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अधिकृत प्रतिनिधि होने का दावा किया, जो ऑस्ट्रेलिया में इसके कानून के तहत निगमित है। आरोपी नंबर 5 ने आरोपी नंबर 1 की ओर से कार्य करने वाले अधिकृत प्रतिनिधि होने का भी प्रतिनिधित्व किया। इन सभी आरोपियों ने शिकायतकर्ता को यह विश्वास दिलाया कि आरोपी नंबर 1 की ओर से उनके द्वारा किए गए लेनदेन में आरोपी नंबर 4 की सहमति थी। यह उनके द्वारा एक-दूसरे के साथ साजिश करके किया गया ताकि गलत तरीके से लाभ कमाया जा सके और शिकायतकर्ताओं को नुकसान पहुंचाया जा सके। उनके अनुसार आरोपी का इरादा 2 दिसंबर, 1998 के समझौते की शर्तों के अनुसार शिकायतकर्ता नंबर 1 द्वारा रखे गए शिकायतकर्ता नंबर 2 के शेयरों की इक्विटी की खरीद के लिए समझौता करने का था, जिसके तहत आरोपी और शिकायतकर्ताओं के बीच यह सहमति हुई थी कि कीमत तय की जाएगी। प्रति शेयर रु. होगा. 7.40 और शिकायतकर्ताओं की कंपनी के शेयरों के अधिग्रहण का लेनदेन निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि उपरोक्त समझौते की शर्तों के अनुसार, आरोपियों को शिकायतकर्ताओं द्वारा अन्य सुविधाओं के अलावा निःशुल्क ट्रांसपोंडर स्पेस का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, हालांकि लाइसेंस अवधि के तहत शिकायतकर्ताओं को सभी ट्रांसॉन्डर स्पेस का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी जो अन्यथा एक थी। दुर्लभ सुविधा को उप-पट्टे पर नहीं दिया जा सका। उन्होंने यह भी बताया कि जब 2 दिसंबर, 1998 को समझौते के बिंदु आरोपी नंबर 1 और 4 द्वारा दर्ज किए गए थे, तो उनका इरादा शिकायतकर्ताओं को धोखा देने का था। अभियुक्तों ने आपराधिक विश्वास हनन का भी अपराध किया क्योंकि अभियुक्तों ने शिकायतकर्ता की ट्रांसपोंडर सुविधाओं का उपयोग करके उनसे संबंधित व्यापार रहस्य और डेटा प्राप्त कर लिया था और उस जानकारी का उपयोग अपने लाभ के लिए किया था। तथ्यात्मक रूप से, आरोपियों ने कभी भी समझौते की शर्तों को पूरा करने का इरादा नहीं किया था, हालांकि वे शिकायतकर्ताओं को झूठा आश्वासन दे रहे थे कि वे 115 दिनों के भीतर अधिग्रहण करेंगे और औपचारिकताओं को पूरा करेंगे, जैसा कि पार्टियों के बीच शुरू में सहमति हुई थी। उन्होंने 15 नवंबर, 1999 की पूर्व सहमति को भी रिकॉर्ड में रखा। पीडब्लू. 1/2 और पीडब्लू. 1/3. उन्होंने आगे कहा कि आरोपी डेढ़ साल के भीतर औपचारिकताओं को पूरा करने में विफल रहे और जब जुलाई 2000 में शिकायतकर्ताओं ने आरोपियों से अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करने के लिए कहा, तो आरोपियों ने ऐसा करने से साफ

इनकार कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा फोन करने का प्रयास किया गया 23 फरवरी, 2000, 11 अप्रैल, 2000, 14 जुलाई, 2000, 16 अगस्त, 2000 और 18 अक्टूबर, 2000 के पत्रों के अनुसार औपचारिकताएं पूरी करने का आरोप लगाया गया (उदा. पीडब्लू. 1/4 से पी.डब्लू. 1/9)। उन्होंने 22 फरवरी, 2000, 2 मार्च, 2000, 10 अप्रैल, 2000 (पूर्व पीडब्लू. 1/10 से पूर्व. पी.डब्लू. 1/12) के पत्रों को भी रिकॉर्ड पर साबित किया। उन्होंने 20 अप्रैल, 2000, 20 अप्रैल, 2000, 20 जुलाई, 2000, 31 अगस्त, 2000 और 26 अक्टूबर, 2000 के पत्रों को भी साबित किया (उदा. पीडब्लू. 1/13 से पीडब्लू 1/16)। कानूनी नोटिस पूर्व. पीडब्लू. 1/17 से पूर्व. पीडब्लू 1/26 को भी रिकॉर्ड पर रखा गया था।

(7) आर.सी. अग्रवाल (पीडब्लू-2) आरपीजी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के उपाध्यक्ष वित्त के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पूर्व दस्तावेज़ देखे हैं। पीडब्लू. 1/1 से पूर्व. पीडब्लू. 1/27 जिस पर पारस के चौधरी और आरोपी नंबर 5 के हस्ताक्षर हैं जो उनकी उपस्थिति में हस्ताक्षरित किए गए थे। आगे उनके अनुसार एमओयू एक्स. पीडब्लू. 1/2 पर पारस के. चौधरी और अबू डब्ल्यू.एम. के हस्ताक्षर हैं। शफ़क़त, आरोपी नंबर 2, जिस पर उनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए थे। उन्होंने नेटवर्क सेवा अनुबंध पूर्व के अलावा उक्त एमओयू के अनुलग्नक को भी साबित किया। पीडब्लू. 1/3 पारस के. चौधरी और अबू डब्ल्यू.एम. द्वारा निष्पादित। शफ़क़त, आरोपी नंबर 2. उसने पूर्व के पत्रों को भी साबित किया। पीडब्लू. 1/4 से पीडब्लू. 1/7 जो आरपीजी एंटरप्राइजेज द्वारा आरोपियों को संबोधित किया गया था और पारस के. चौधरी के हस्ताक्षरों की पहचान की गई थी। उन्होंने दावा किया कि ये पत्र उनकी उपस्थिति में हस्ताक्षरित और भेजे गए थे। उन्होंने पूर्व दस्तावेज़ भी सिद्ध किये। पीडब्लू. 1/8, उदा. पीडब्लू 1/9, पीडब्लू. 1/11, पीडब्लू. 1/12 पीडब्लू को। 1/13. पूर्व. पीडब्लू. 1/14 और पी.डब्ल्यू 1/16, पीडब्लू 1/17। पीडब्लू. 1/23, पीडब्लू. 1/24, पीडब्लू. 1/19, पीडब्लू. 1/20, पीडब्लू. 1/21, पीडब्लू पीडब्लू। 1/25, पीडब्लू. 1/26 और पूर्व. पीडब्लू 1/27.

(8) शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक साक्ष्य के आधार पर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुड़गांव ने 22 मई, 2001 के आदेश के अनुसार प्रथम दृष्टया निष्कर्ष निकाला कि उपरोक्त सभी नामित आरोपियों ने धारा 406, 420 और के तहत अपराध किया था। 120-बी धारा 34 आईपीसी के साथ पठित। और तदनुसार उन्हें उपरोक्त अपराधों के संबंध में अपने न्यायालय में मुकदमे

का सामना करने के लिए बुलाया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर सभी छह नामित आरोपियों द्वारा वर्तमान याचिकाएं दायर की गई थीं।

(9) शिकायत को रद्द करने और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुड़गांव द्वारा याचिकाकर्ता-अभियुक्तों के खिलाफ 22 मई, 2001 को पारित समन आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए, याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा यह आग्रह किया गया था कि शिकायत को ध्यान से पढ़ा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि यह पार्टियों के बीच निष्पादित दस्तावेजों के कुछ हिस्से को एक विकृत तस्वीर पेश करने कि लिए जो समझौते की शर्तों से उत्पन्न हुआ था ताकि उनके खिलाफ हेराफेरी, धोखाधड़ी और साजिश का मामला बनाया जा सके जो तथ्यात्मक रूप से रिकॉर्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजों से सामने नहीं आया है। प्रारंभिक साक्ष्य के दौरान शिकायतकर्ताओं का पक्ष। विशेष रूप से दिनांक 2 दिसंबर, 1998 के लेखन का उल्लेख किया गया था जिसे समझौते के बिंदु (अनुलग्नक-पी. 4), एमओयू दिनांक 15 नवंबर, 1999 (अनुलग्नक-पी. 5) और नेटवर्क सेवा समझौता दिनांक 15 नवंबर, 1999 (अनुलग्नक) कहा गया था। -पी. 6) जो पार्टियों के अधिकारों को पारदर्शी रूप से सामने लाता है। उनके द्वारा स्पष्ट रूप से आग्रह किया गया था कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी नंबर 2 और 3 को अग्रिम भुगतान किया था, जिन्होंने नेटवर्क सेवा समझौते को अवैध रूप से समाप्त करके धोखाधड़ी की थी। उनके द्वारा आग्रह किया गया कि यह प्रतिवादी नंबर 3 था, जिसे रुपये की बकाया राशि का भुगतान करना आवश्यक था। याचिकाकर्ता नंबर 1 को 21% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 42,06,103 रु. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उक्त एमओयू और एनएसए में कोई अस्पष्टता नहीं है। समझौते की समाप्ति की शर्तों वाले एनएसए (अनुलग्नक-पी. 6) के खंड 3 को पढ़ने से पता चलेगा कि उसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि समझौता तीन स्थितियों में समाप्त हो जाएगा। एक शेयर खरीद समझौते का पहले पूरा होना था। दूसरा विकल्प यह था कि जमा की गई राशि को मासिक भुगतान से पूरी तरह से हटा दिया जाएगा और याचिकाकर्ताओं के लिए तीसरा विकल्प दो दिन के नोटिस के किसी भी समय समझौते को समाप्त करने के लिए उपलब्ध था। आगे 2 दिसंबर 1998 के समझौते के बिंदुओं का संदर्भ दिया गया था जो स्पष्ट रूप से उस आधार को इंगित करता है जिस पर पार्टियों के बीच बातचीत समय सीमा के भीतर पूरी की जानी थी और इसका उद्देश्य केवल प्रतिवादी नंबर 3 के शेयर की खरीद की संभावना तलाशना था। प्रतिवादी नंबर 2. यही कारण है कि समय सीमा से निपटने के दौरान, एक टर्म शीट पर हस्ताक्षर करने के संदर्भ में समझौता विशेष रूप से किया गया था जो एक

दस्तावेज के अलावा और कुछ नहीं है जिसके तहत शेयरों के हस्तांतरण की शर्तें तय की जाएंगी। इस प्रकार, यह एक दस्तावेज़ नहीं था जिसे पार्टियों के बीच शेयरों के हस्तांतरण के लिए एक पूर्ण अनुबंध कहा जा सकता है। इस दस्तावेज़ में नियोजित "डु डिलिजेंस" शब्दों का उल्लेख करते हुए, यह कहा गया था कि यह एक स्पष्ट रूप से परिभाषित वाणिज्यिक शब्द का प्रतीक है जो पार्टी को वित्तीय और कानूनी विशेषज्ञ के माध्यम से व्यवसाय या वाणिज्यिक ऑडिट करने की अनुमति देता है। इस तरह के अभ्यास का मूल विचार संरक्षित करना है भाग को उचित परिश्रम करने और फिर उस पर आगे निर्णय लेने की स्वतंत्रता है विशेषज्ञों द्वारा दी गई सलाह के आधार पर। इस प्रकार, यह दूर-दूर तक नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि शिकायतकर्ताओं की ओर से अनुमान लगाने की कोशिश की गई थी कि 2 दिसंबर, 1998 का समझौता शेयरों के हस्तांतरण के लिए पार्टियों के बीच किया गया एक समझौता था। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुत किया गया कि मुख्य तथ्य यह है कि पार्टियों ने 15 नवंबर, 1999 को एमओयू निष्पादित करने के लिए चुना था (अनुलग्नक-पी.5) आगे इंगित करता है कि पार्टियों ने केवल अधिग्रहण की संभावना पर बातचीत करने के लिए समझौता किया था और जो भी अधिकार अस्तित्व में आए थे 2 दिसंबर 1998 के समझौते को इस दस्तावेज़ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यही कारण है कि खंड 1 के तहत "स्कोप 1.1" शीर्षक के तहत यह कहा गया था कि उनके एमओयू ने उस तरीके को निर्धारित किया है जिसमें पार्टियां खंड 2 में संदर्भित प्रस्तावित लेनदेन पर बातचीत करने का इरादा रखती हैं। इस तरह पार्टियों ने शेयरों के संभावित हस्तांतरण के लिए बातचीत करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया था। इसके अलावा खंड 4.3 में कहा गया है कि शेयरों के लिए भुगतान की जाने वाली वास्तविक कीमत प्रतिवादी नंबर 2 और आरोपी नंबर 1 के बीच बातचीत से निर्धारित की जाएगी, जो अन्य बातों के अलावा, परिणाम को ध्यान में रखते हुए वर्तमान याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं में से एक है। याचिकाकर्ताओं की वित्तीय, तकनीकी और कानूनी उचित परिश्रम। ये विवरण स्पष्ट रूप से प्रदान करते हैं कि कीमत का महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण घटक इस समझौते के तहत परिकल्पित लघु में निर्धारित किया जाना बाकी था। यही कारण है कि खंड 6 जो उचित परिश्रम से संबंधित है, ने आरोपी नंबर 1 को व्यापक विकल्प दिया था। याचिकाकर्ताओं के वकील के अनुसार, आगे खंड 8, 9 और 10, किसी भी तरह से एमओयू की आवश्यक प्रकृति को नहीं बदलते हैं। खंड 15 स्पष्ट रूप से पार्टियों के बीच "कोई बाध्यकारी दायित्व नहीं" निर्दिष्ट करता है। उनके द्वारा इस बात पर प्रकाश डाला गया कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के पास इस रुख को साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि

अनुबंध का कोई उल्लंघन हुआ था या मामले की परिस्थितियों के तहत कार्रवाई का कोई कारण हुआ था।

(10) याचिकाकर्ताओं की ओर से जिन अतिरिक्त परिस्थितियों का उल्लेख किया गया था, वे हैं कि आरपीजी टेलीफोन्स लिमिटेड, प्रतिवादी नंबर 2 और टीवीसीएल दोनों भारत में वीएसएटी सेवा के लाइसेंस प्राप्त प्रदाता थे। प्रतिवादी संख्या 2 और 3 ने 15 नवंबर 1999 की कॉर्पोरेट गारंटी के बारे में दायर शिकायत में जानबूझकर खुलासा नहीं किया था और इस प्रकार वे न्यायालय से महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने के दोषी हैं। प्रतिवादी संख्या 2 और 3 ने भी अदालत से जानकारी रोक ली थी क्योंकि शिकायत संख्या में उल्लेख किया गया था कि उन्होंने नेटवर्क सेवा समाप्त कर दी है दिनांक 26 नवंबर, 2000 को टेलीग्राम द्वारा समझौता (अनुलग्नक-पी)। 10) टीवीसीएल द्वारा आपराधिक विविध में रिकॉर्ड पर रखा गया। 2001 की संख्या 26225-एम जिसके बाद दिनांक 14 नवंबर, 2000 का पत्र (अनुबंध-पी. 8) और 16 नवंबर, 2000 का एक अन्य पत्र (अनुलग्नक-पी. 9) उपरोक्त उल्लिखित याचिका में रिकॉर्ड पर रखा गया।

(11) अबू डब्ल्यू.एम. की ओर से। शफ़क़त, याचिकाकर्ता, को शिकायत में आरोपी नंबर 2 के रूप में प्रस्तुत किया गया था, यह कहा गया था कि वह ए 15, हैव्स बार्टन वर्किंग सर्वे, इंग्लैंड, यू.के. में स्थित एक अनिवासी भारतीय है। प्रासंगिक समय पर, वह टेल्स्ट्रा विशेष के साथ काम कर रहा था। कम्युनिकेशंस लिमिटेड, नई दिल्ली 2 अक्टूबर, 1995 से उपाध्यक्ष (बिक्री और विपणन) के रूप में। उन्हें इस समझ पर टेल्स्ट्रा विशेष कम्युनिकेशन लिमिटेड (संक्षिप्त टीवीसीएल के लिए) के निदेशक मंडल के निदेशक के रूप में नामित किया गया था कि वह प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दे देंगे। यथाशीघ्र सहमत तिथि के प्रभाव से और टीवीसीएल के अनुरोध पर, यह सहमति हुई कि याचिकाकर्ता दिनांक 11.07.2017 से टीवीसीएल के प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दे देगा। 15 नवंबर, 1999 और उसके बाद से उनका टीवीसीएल से कोई सरोकार नहीं रहेगा। उनके अनुसार टेल्स्ट्रा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के पास टीवीसीएल के 47.1% शेयर हैं। वीडियो संचार निगम लिमिटेड के पास टीवीसीएल के 33.3% शेयर हैं और शेष 19.6% शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के पास हैं। उनके रुख के अनुसार, बाद के दो शेयरधारक अधिनियम के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनियां हैं। 15 नवंबर, 1999 से, याचिकाकर्ता किसी भी तरह से टीवीसीएल से जुड़ा नहीं है और वर्तमान में वह यूके में एक कंपनी में कार्यरत है। इस प्रकार, टीवीसीएल से कोई लेना-देना नहीं होने के कारण, उसे टीवीसीएल के साथ शिकायत में बुलाया गया है। बिना किसी आधार

के शिकायत में तलब किया गया है। साथ ही, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा इस बात पर कोई विवाद नहीं किया गया कि याचिकाकर्ता ने टीवीसीएल के प्रबंध निदेशक की क्षमता में बातचीत और चर्चा में भाग लिया था और निर्देश के तहत टीवीसीएल के प्रतिनिधि के रूप में 15 नवंबर, 1999 के एमओयू को निष्पादित किया था। टीवीसीएल के निदेशक मंडल के. यह भी प्रस्तुत किया गया कि पहले बताए गए कारणों के लिए उन पर कोई देनदारी नहीं थी क्योंकि रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेज़ आयोग में उनकी शिकायत में बताए गए अपराध में भागीदारी को स्थापित नहीं करते हैं।

(12) पुष्पेंद्र एस मांकड़ ने अपनी याचिका में कोई विवाद नहीं किया था कि वह टेल्स्ट्रा विशेष कम्युनिकेशन के मुख्य कार्यकारी हैं लिमिटेड, आरोपी नंबर 1. टेल्स्ट्रा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरोपी नंबर 4 यह ऑस्ट्रेलिया के कानूनों के तहत निगमित एक कंपनी है मैन्सफील्ड में पंजीकृत कार्यालय। डेरिल स्मिथ, आरोपी नंबर 5, सिडनी में आरोपी नंबर 4 के निदेशक और आरोपी नंबर 6 सिग सोविक सिडनी में आरोपी नंबर 4 के महाप्रबंधक हैं। इन याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे टीवीसीएल के शेयर धारक भी नहीं हैं और प्रतिवादी नंबर 2 और 3 के साथ उनका कोई अनुबंध नहीं था। इन याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया था कि आरोपी नंबर 4 या उसके कोई भी निदेशक इसमें पक्षकार नहीं थे। प्रतिवादी संख्या 2 और 3 और टीवीसीएल के बीच समझौते पर बातचीत या हस्ताक्षरकर्ता। यह भी तर्क दिया गया कि टेल्स्ट्रा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड प्रतिवादी नंबर 2, 3 और टीवीसीएल के बीच निष्पादित किए गए किसी भी दस्तावेज का हस्ताक्षरकर्ता भी नहीं है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि रिकॉर्ड पर लाए गए तथ्य और रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेज़ याचिकाकर्ताओं और टेल्स्ट्रा होडिंग प्राइवेट लिमिटेड को कथित अपराध के कमीशन से दूर-दूर तक नहीं जोड़ते हैं।

(13) प्रतिवादी संख्या 2 और 3 का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अपने तर्कों के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अपनाए गए रुख का खंडन और विरोध करते हुए शिकायत में बताए गए तथ्यों और याचिकाकर्ताओं-आरोपी के आधार पर किए गए आरोपों को दोहराया और उचित ठहराया। शिकायत में लगाए गए आरोपों के समर्थन में पेश किए गए प्रारंभिक सबूतों के कारण ऊपर उल्लिखित अपराध के संबंध में याचिकाकर्ता-अभियुक्तों को तलब किया गया। याचिकाकर्ता-अभियुक्त की ओर से अपनाए गए रुख का खंडन करते हुए कि 15 नवंबर, 1999 की कॉर्पोरेट गारंटी के तथ्य और टेलीग्राम के रूप में समाप्ति पत्र को शिकायत में दबा दिया

गया था, उनके द्वारा स्पष्ट रूप से आग्रह किया गया था कि इसमें निहित शर्तें शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा भेजे गए 15 नवंबर, 1999 के एमओयू और 14 नवंबर, 2000 और 16 नवंबर, 2000 के नोटिस के साथ विस्तार से बताया गया कि धोखाधड़ी के स्पष्ट इरादे से याचिकाकर्ता-अभियुक्त द्वारा किए गए झूठे प्रतिनिधित्व और प्रलोभन के कारण शिकायतकर्ताओं, नेटवर्क सेवा अनुबंध और उसके तहत दी गई सभी गारंटियां अमान्य हो जाएंगी और इस कारण से याचिकाकर्ताओं द्वारा शिकायतकर्ताओं-उत्तरदाताओं पर की गई धोखाधड़ी को देखते हुए गारंटियां लागू नहीं की जा सकेंगी। साथ ही, प्रतिवादियों की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि तथ्यात्मक रूप से टर्म शीट को एमओयू के रूप में निष्पादित किया गया था और समझौते में निर्धारित उचित परिश्रम पूरा किया गया था और इसके बाद ही आरोपी नंबर 3 ने भाग लेना शुरू किया। शिकायतकर्ता क्रमांक 2 की बोर्ड बैठक में किस तथ्य का समर्थन किया जा सकता है शिकायतकर्ताओं के रिकॉर्ड के आधार पर. का जिक्र करते हुए टीसीसीएल, याचिकाकर्ता-अभियुक्त नंबर 1 द्वारा स्वीकारोक्ति कि यह एक कंपनी है, जिसमें टेल्स्ट्रा के पास 47.1% शेयर हैं, आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 4 के बीच स्पष्ट सांठगांठ रिकॉर्ड पर दर्ज की गई है और यह आरोपी नंबर 1 और 4 और उसके अधिकारियों के बीच मिलीभगत के कारण है कि धोखाधड़ी और धोखाधड़ी की गई थी शिकायतकर्ताओं पर. उत्तरदाताओं के अनुसार पार्टियों के बीच अनुबंध की गोपनीयता 2 दिसंबर, 1998 के समझौते के बिंदुओं के निष्पादन के आधार पर अस्तित्व में आई थी, जिस पर डेरिल स्मिथ, आरोपी नंबर 5, जो आरोपी नंबर के निदेशक थे, द्वारा हस्ताक्षरित और निष्पादित किया गया था। 4. उन्होंने आरोपी नंबर 1 याचिकाकर्ता और आरोपी नंबर 4 का भी प्रतिनिधित्व किया था क्योंकि वे शिकायतकर्ता कंपनी की 100% शेयर होल्डिंग्स खरीदने में रुचि रखते थे और यह आरोपी नंबर 5 द्वारा दिए गए आश्वासन के कारण था कि दस्तावेज़ निष्पादित किए गए थे। पार्टियों के बीच. रिकॉर्ड नोटिस पर प्रस्तुत कई पत्रों का भी संदर्भ दिया गया था, जिन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुड़गांव ने प्रतिवादी-शिकायतकर्ताओं द्वारा उठाए गए रुख का समर्थन करने के लिए सम्मन आदेश में लिया था। इन परिस्थितियों के आधार पर, उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने याचिकाकर्ता-अभियुक्त द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करने की प्रार्थना की।

(14) इस स्तर पर, उन मापदंडों पर ध्यान देना उचित होगा जिन्हें शिकायत को रद्द करने और आरोपी के खिलाफ पारित समन आदेश के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने मामलों की श्रृंखला में स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक चरण में

कार्यवाही को रद्द करने की पुनरीक्षण या अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कम से कम और केवल तभी किया जाना चाहिए जहां शिकायत या एफआईआर में लगाए गए आरोप, यहां तक कि उनके अंकित मूल्य पर भी लिए गए हों और पूरी तरह से स्वीकार किए गए हों। , प्रथम दृष्टया अपराध के घटित होने का खुलासा न करें। विवादित एवं विवादस्पद तथ्यों को ऐसे क्षेत्राधिकार के प्रयोग का आधार नहीं बनाया जा सकता।

(15) आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य (ए.आई.आर 1960 एस.सी. 866) में यह निर्धारित किया गया था:

"यह अच्छी तरह से स्थापित है कि उच्च न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का उपयोग किसी उचित मामले में कार्यवाही को रद्द करने के लिए किया जा सकता है या तो किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। आमतौर पर किसी आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है व्यक्ति पर संहिता के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए, और उच्च न्यायालय अंतरिम चरण में उक्त कार्यवाही में हस्तक्षेप करना। किसी भी अनम्य नियम को निर्धारित करना संभव, वांछनीय या समीचीन नहीं है जो इस अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के अभ्यास को नियंत्रित करेगा। हालाँकि, हम कुछ श्रेणियों के मामलों पर आरोप लगा सकते हैं जहाँ कार्यवाही को रद्द करने के लिए अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां उच्च न्यायालय के लिए यह विचार करना संभव हो सकता है कि किसी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करना या जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो सकता है या विवादित कार्यवाही को रद्द करना सुरक्षित होगा न्याय का अंत. यदि विचाराधीन आपराधिक कार्यवाही किसी आरोपी व्यक्ति के संबंध में है और यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि संस्था के खिलाफ या उक्त कार्यवाही जारी रखने में कोई कानूनी बाधा है, तो उच्च न्यायालय द्वारा उस आधार पर कार्यवाही को रद्द करना उचित होगा। उदाहरण के लिए, अपेक्षित मंजूरी के अभाव में इस श्रेणी के अंतर्गत मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ऐसे मामले भी उत्पन्न हो सकते हैं जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया गया हो, कथित अपराध का गठन नहीं करते हैं; ऐसे मामलों में साक्ष्य की सराहना का कोई सवाल ही नहीं उठता; यह केवल शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट को देखने का मामला है ताकि

यह तय किया जा सके कि कथित अपराध का खुलासा किया गया है या नहीं। ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय के लिए यह मानना वैध होगा कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक अदालत की प्रक्रिया जारी करने की अनुमति देना स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण होगा। मामलों की एक तीसरी श्रेणी भी उत्पन्न हो सकती है जिसमें उच्च न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मामलों में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप कथित अपराध का गठन करते हैं लेकिन मामले के समर्थन में या तो कोई कानूनी सबूत पेश नहीं किया जाता है या सबूत स्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से आरोप साबित करने में विफल रहता है। इस वर्ग के मामलों से निपटने में ऐसे मामले के बीच अंतर को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है जहां कोई कानूनी सबूत नहीं है या जहां कोई कानूनी सबूत नहीं है या फिर जहां ऐसा साक्ष्य है जो स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से लगाए गए आरोप से असंगत है और ऐसे मामले जहां कानूनी साक्ष्य हैं जो इसकी सराहना पर प्रश्न में आरोप का समर्थन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। धारा 561-ए के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय इस बात की जांच नहीं करेगा कि विचाराधीन साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं। यह ट्रायल मजिस्ट्रेट का कार्य है, और आमतौर पर यह किसी भी पक्ष के लिए उच्च न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का आह्वान करने और यह तर्क देने के लिए खुला नहीं होगा कि सबूतों की उचित सराहना के बावजूद आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप कायम नहीं रहेंगे। मोटे तौर पर यह कहा गया है कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के मामले में धारा 561-ए के तहत उच्च न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार की प्रकृति और दायरा है, और यही इस बिंदु पर न्यायिक निर्णयों का प्रभाव है।"

(16) उपरोक्त निर्णय का पालन *हजारी लाल गुप्ता बनाम रामेश्वर प्रसाद* (एआईआर 1972 एससी 484), *कर्नाटक राज्य बनाम एल मुनिस्वामी*, (एआईआर 1977 एससी 1489) *हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल*, (एआईआर 1992 एससी 604) अंतिम मामले में किया गया था। इस संबंध में न्यायालयों के लिए दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं:-

> *"(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें अंकित मूल्य पर लिया गया हो और पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है।*

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफआईआर के साथ संलग्न अन्य सामग्रियों में आरोप, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है। संहिता की धारा 155(2) के दायरे में।

(3) जहां शिकायत या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी के भी कमीशन का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

(4) जहां, एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल गैर-संज्ञेय अपराध हैं, वहां मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है, जैसा कि संहिता की धारा 155 (2) में माना गया है।

(5) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के प्रावधानों में एक स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई है, वहां कार्यवाही शुरू करने और जारी रखने पर, जहां संबंधित अधिनियम की संहिता में एक विशिष्ट प्रावधान हैं।, पीड़ित पक्ष की शिकायत का प्रभावी समाधान प्रदान करना।

(7) जहां कोई आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना से की गई हो और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से अभियुक्त पर प्रतिशोध लेने और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के लिए की गई हो।"

(17) उपर्युक्त में प्रतिपादित सिद्धांतों का पालन रूपण देवल बाजव में भी किया गया है। कंवर पाल एस गिल, (1995 एससीसी (सीआरएल) 1059) राजेश बजाज बनाम स्टेट एनसीटी ऑफ डेली, (1999 एससीसी (सीआरएल) 401) स्टेट ऑफ के बनाम ओ.सी. कुट्टन, (1999 एससीसी

(सीआरएल) 304) पी.एस. राज्य बनाम बिहार राज्य, (1996 एससीसी (सीआरएल) 897) स्टा उड़ीसा बनाम बंसीधर सिंह, (1996 एससीसी (सीआरएल) 259)

18) इस संबंध में राज्य बिहार बनाम मोहम्मद खालिक और अन्य, ((2002) 1 एससीसी 652) कमलादेवी अग्रवाल राज्य पश्चिम बंगाल का भी संदर्भ दिया जा सकता है। और अन्य ((2002) 1 एससीसी 555 23)), एम. कृष्णन बनाम विजय सिंह और अन्य, ((2002) एससीसी (सीआरएल) 19) दिनेश दत्त जोशी बनाम राजस्थान राज्य, ((2002) एससीसी (सीआरएल) 24) एम. दमानी बनाम एस.के. सिन्हा और अन्य (2001 (5) एससीसी 156) ओम वती (श्रीमती) और अन्य बनाम राज्य दिल्ली प्रशासन के माध्यम से। और अन्य, (2001 4 एससीसी 333) लालमुर देवी (श्रीमती) बनाम बिहार राज्य और अन्य, (2001 2 एससीसी 17) मराट रूबे लिमिटेड बनाम जे.के. मराट्टुकलम, (2000 9 एससीसी 547) प्रूडेंशियल कैपिटल एमके लिमिटेड और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, (2000 9 एससीसी 539) महाव प्रसाद गुप्ता और अन्य बनाम नेशनल कैपिटो टेरिटरी ऑफ दिल्ली राज्य और अन्य, (2000 8 एससीसी 115) मेडचल केमिकल्स एंड फार (पी) लिमिटेड वी. बायोलॉजिकल ई. लिमिटेड और अन्य, (2000 3 एससीसी 269) और त्रिसूर केमिकल इंडस्ट्री बनाम राजेश अग्रवाल और अन्य, (1999 8 एससीसी 686)।

(19) आगे हृदय रंजना प्रसाद वर्मा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, (एआईआर 2000 एससी 2341), अल्फिक फाइनेंस लिमिटेड बनाम पी. सदाशिवन (जेटी 2001(2) एससी 588 3) जी. सागर सूरी उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (जेटी 2000(1) एससी 360) का संदर्भ दिया जा सकता है। सुनील कुमार बनाम एस्कोर यामाहा और अन्य, (जेटी 2000(1) एससी 360), माधवराव सिंधिया और अन्य, संभाजीराव आंग्रे और अन्य, (एआईआर 1988 एससी 709) मंजू गुप्ता बनाम एम.एस. पेंटो (एआईआर 1982 एससी 1181), अशोक चतुर्बेदी और अन्य बनाम शितुल एच. चंचन (एआईआर 1982 एससी 2796), पेप्सी फूड्स लिमिटेड और अन्य बनाम सिपाही न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य (एआईआर 1998 एससी 128), पंजाब आनंद लैंप इंडस्ट्री लिमिटेड बनाम असाही वीडियो प्राइवेट लिमिटेड (1999 (1) आरसीआर (सीआरएल) 601), मैसर्स कुन्स्टोको इलेक्ट्रॉनिक्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड बनाम गिल्ट पैक लिमिटेड और अन्य (जेटी 2000(1) एससी 268) , और कर्नाटक राज्य बनाम मुनिस्वामी (उपरोक्त लिखित)।

(20) उपरोक्त उल्लिखित मामलों में अदालत के समक्ष लाए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, स्पष्ट सिद्धांत पर जोर दिया गया है नागरिक प्रकृति और दायरे का प्रतीत होता है। आपराधिक कार्यवाही और मामलों में आवश्यक सबूत के मानक अलग और विशिष्ट हैं जिन्हें उस चरण में भी ध्यान में रखा जाना चाहिए जहां एफआईआर और समन आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की जाती है। यद्यपि न्यायालय में निहित शक्ति का प्रयोग असाधारण और दुर्लभतम मामलों में संयमित ढंग से किया जाना है, साथ ही, न्यायालय आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देगा जहां खुलासा किए गए तथ्य इस तरह के सहारा की गारंटी नहीं देते हैं क्योंकि ऐसी आपराधिक कार्यवाही जारी रखने के बराबर होगी। न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करना। यही कारण है कि उपर्युक्त मामलों में यह दोहराया गया है कि जहां मामला अनिवार्य रूप से नागरिक प्रकृति का है, लेकिन इसे आपराधिक अपराध का जामा पहना दिया गया है, अदालत शिकायतकर्ता को उपचार के रूप में आपराधिक अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं देगी। कानून में उपलब्ध है. यही कारण है कि न्यायालय पर इस बात पर जोर दिया गया है कि कोई भी प्रक्रिया जारी करने से पहले उसे बहुत सावधानी बरतनी होगी क्योंकि किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाना गंभीर मामला है जैसा कि पेप्सी फूड्स लिमिटेड और अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य में उजागर किया गया है। उपर्युक्त मामले में की गई प्रासंगिक टिप्पणियाँ निर्णय के पैरा 28 में निहित हैं जो निम्नानुसार हैं:-

"आपराधिक मामले में किसी आरोपी को तलब करना एक गंभीर मामला है। आपराधिक कानून को यूं ही लागू नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि शिकायतकर्ता को अपराधी को पकड़ने के लिए शिकायत में अपने आरोपों के समर्थन में केवल दो गवाह लाने होंगे।" कानून लागू हो गया। आरोपी को बुलाने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश में यह प्रतिबिंबित होना चाहिए कि उसने मामले के तथ्यों और उस पर लागू कानून पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। उसे शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रकृति और मौखिक साक्ष्य दोनों की जांच करनी होगी और उसके समर्थन में वृत्तचित्र और क्या यह शिकायतकर्ता के लिए आरोपी तक आरोप पहुंचाने में सफल होने के लिए पर्याप्त होगा। ऐसा नहीं है कि मजिस्ट्रेट आरोपी को बुलाने से पहले प्रारंभिक साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के समय मूक दर्शक है। मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए और आरोपों की सत्यता या अन्यथा पता लगाने के लिए उत्तर पाने के लिए शिकायतकर्ता और उसके गवाहों से खुद भी सवाल पूछ सकते

हैं और फिर जांच कर सकते हैं कि क्या कोई अपराध प्रथम दृष्टया सभी या किसी भी आरोपी द्वारा किया गया है। ।"

(21) इस स्तर पर नागवा बनाम वीरन्ना शिवलिंगप्पा कोंजाल्गी, (1976 एससीसी (सीआरएल.) 507) मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर भी ध्यान देना होगा, जिसमें यह माना गया था कि आरोपियों के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने के मजिस्ट्रेट के आदेश को निम्नलिखित के तहत रद्द किया जा सकता है। परिस्थितियाँ

"(1) जहां शिकायत में लगाए गए आरोप या उसके समर्थन में दर्ज किए गए गवाहों के बयान, उनके अंकित मूल्य पर लिए जाने पर, आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है या शिकायत किसी अपराध के आवश्यक तत्वों का खुलासा नहीं करती है जो कि है आरोपियों के खिलाफ आरोप:

(2) जहां शिकायत में लगाए गए आरोप स्पष्ट रूप से बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, ताकि कोई भी विवेकशील व्यक्ति इस निष्कर्ष पर न पहुंच सके कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है।

(3) जहां जारी करने की प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग किया गया विवेक विवेकहीन और मनमाना है, या तो बिना किसी सबूत के या ऐसी सामग्रियों पर आधारित है जो पूरी तरह से अप्रासंगिक या अस्वीकार्य हैं; और

(4) जहां शिकायत मौलिक कानूनी दोषों से ग्रस्त है, जैसे मंजूरी की कमी, या कानूनी रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा शिकायत की अनुपस्थिति आदि।"

(22) उपर्युक्त मामलों में बताई गई कानून की स्थिति पर ध्यान देते समय, एक पेटेंट तथ्य जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए वह यह है कि मूल रूप से विवाद का निर्णय इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना है क्योंकि वे हैं वास्तविक आधार जो उस न्यायालय को पक्षों के बीच उत्पन्न हुए विवाद को निपटाने में सक्षम बनाएगा।

(23) याचिकाकर्ताओं पर आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 415, 420, 406, 120-बी के तहत मुकदमा चलाने की मांग की जा रही है, इन अपराधों के आवश्यक तत्वों पर ध्यान देना प्रारंभिक रूप से आवश्यक है। इस में हृदय रंजब प्रसाद वर्मा और अन्य बनाम बिहार राज्य

और अन्य (सुप्रा) मामले में फैसले के पैरा 13 से 15 में निहित चर्चा को संदर्भित करने की आवश्यकता है। उसमें इस प्रकार कहा गया था

"13. धोखाधड़ी को संहिता की धारा 415 में इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

415. जो कोई, किसी व्यक्ति को धोखा देकर, धोखे से या बेईमानी से उस व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को देने के लिए प्रेरित करता है, या सहमति देने के लिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति को बनाए रखेगा, या जानबूझकर ऐसे धोखेबाज व्यक्ति को कुछ भी करने या न करने के लिए प्रेरित करता है यदि उसे धोखा न दिया गया हो तो वह ऐसा नहीं करेगा या छोड़ देगा, और जिस कार्य या चूक से उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान या नुकसान होने की संभावना है, उसे 'धोखा' कहा जाता है।

स्पष्टीकरण। तथ्यों को बेईमानी से छिपाना इस धारा के अर्थ में एक धोखा है।"
अनुभाग की आवश्यकता है-
(1) किसी व्यक्ति से धोखा :
(2) (ए) उस व्यक्ति को धोखे से या बेईमानी से प्रेरित करना
(i) किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति वितरित करना, या
(ii) इस बात पर सहमति देना कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति को बनाए रखेगा या (बी) जानबूझकर उस व्यक्ति को ऐसा कुछ भी करने या करने के लिए प्रेरित करना जो वह करता या छोड़ देता यदि उसे धोखा नहीं दिया गया होता, और कौन सा कार्य या चूक उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है या नुकसान पहुंचाने की संभावना है या संपत्ति।

14. अनुभाग को पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि परिभाषा में कार्यों के दो अलग-अलग वर्ग निर्धारित किए गए हैं जिन्हें धोखा देने वाले व्यक्ति को करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। सबसे पहले, उसे धोखे से या बेईमानी से किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अनुभाग में उल्लिखित कृत्यों का दूसरा वर्ग करना या ऐसा कुछ भी करने से चूक जाना जिसे धोखा दिया गया व्यक्ति

नहीं करता या यदि उसे धोखा न दिया गया होता तो वह ऐसा करने से चूक जाता। प्रथम श्रेणी के मामलों में उत्प्रेरण कपटपूर्ण या बेईमान होना चाहिए। कृत्यों के दूसरे वर्ग में, उत्प्रेरण जानबूझकर होना चाहिए लेकिन कपटपूर्ण या बेईमान नहीं होना चाहिए।

15. प्रश्न का निर्धारण करते समय यह ध्यान में रखना होगा कि मात्र अनुबंध के उल्लंघन और धोखाधड़ी के अपराध के बीच अंतर ठीक है। यह उत्प्रेरण के समय अभियुक्त के इरादे पर निर्भर करता है जिसे उसके बाद के आचरण से आंका जा सकता है लेकिन इसके लिए बाद का आचरण ही एकमात्र परीक्षण नहीं है। केवल अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता है जब तक कि लेनदेन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा नहीं दिखाया जाता है, यही वह समय है जब अपराध किया गया माना जाता है। इसलिए यह इरादा ही है जो अपराध का सार है। किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी का दोषी ठहराने के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि वादा करते समय उसका इरादा धोखाधड़ी या बेईमानी का था। वादा पूरा करने में उनकी असफलता के बाद शुरुआत में ही, यानी जब उन्होंने वादा किया था, ऐसा दोषपूर्ण इरादा नहीं माना जा सकता है।"

(24) जी.वी. में. राव बनाम एल.एच.वी. प्रसाद और अन्य (2000(2) आरसीआर (सीआरएल) 290 (एससी)), पैरा 7 में, शीर्ष न्यायालय द्वारा इसे निम्नानुसार कहा गया था-

"जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा 415 के दो भाग हैं। जबकि पहले भाग में, व्यक्ति को शिकायतकर्ता को "बेईमानी से" या "कपटपूर्ण तरीके से" किसी भी संपत्ति को वितरित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, दूसरे भाग में व्यक्ति को जानबूझकर शिकायतकर्ता को ऐसा करने या छोड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए एक कार्य करने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि, पहले भाग में, प्रलोभन बेईमानी या धोखाधड़ी वाला होना चाहिए। दूसरे भाग में, प्रलोभन जानबूझकर होना चाहिए। जैसा कि इस न्यायालय ने जसवन्तराय मणिलाल अखाने बनाम बॉम्बे राज्य, एआईआर 1956 में देखा था एससी 575 एक गंदा इरादा धोखाधड़ी के अपराध का एक अनिवार्य घटक है। इसलिए, धोखाधड़ी के अपराध के लिए किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए, उस व्यक्ति की ओर से 'मनुष्य के कारण' को स्थापित किया जाना चाहिए। यह

महादेव प्रसाद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, एआईआर 1954 एससी 724 में भी देखा गया था कि धोखाधड़ी का अपराध गठित करने के लिए, धोखा देने का इरादा उस समय अस्तित्व में होना चाहिए जब प्रलोभन की पेशकश की गई थी।"

(25) कानून की स्थिति पर ध्यान देने के बाद, मामले के तथ्यों का मूल्यांकन दोहराव के जोखिम पर भी किया जाना चाहिए ताकि पार्टियों द्वारा उठाए गए संबंधित स्टैंड के आधार पर विवाद के मूल तक पहुंचा जा सके। इस मामले में स्वीकृत तथ्य यह है कि टीवीसीएल, आरोपी नंबर 1 एक कंपनी है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के कानूनों के तहत पंजीकृत टेल्स्ट्रा के पास 47.1% शेयर हैं। इसके अलावा विदेश संचार निगम लिमिटेड के पास 33.3% शेयर हैं और शेष 19.6% शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के पास हैं। बाद के दो शेयरधारक कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनियां हैं। यह भी विवादित नहीं है। शिकायतकर्ता नंबर 1 आरपीजी टेलीफोन्स लिमिटेड और टीवीसीएल दोनों भारत में वीएसएटी सेवा के लाइसेंस प्राप्त प्रदाता हैं। इसलिए, वे दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के साथ अपने संविदात्मक दायित्वों के संबंध में पूरी तरह से अवगत हैं, शिकायतकर्ता नंबर-1 कंपनी के पास शिकायतकर्ता नंबर-2-कंपनी के 100% शेयर हैं और वह उक्त शेयरों के लाभकारी मालिक हैं। इस कारण से शिकायतकर्ता नंबर 1 शिकायतकर्ता नंबर 2 की कंपनी का मालिक है। शिकायतकर्ताओं ने शिकायत में स्वीकार किया था कि दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा उसे दिए गए लाइसेंस के संदर्भ में, वह उप-नहीं कर सकता है। किसी अन्य निकाय को किसी भी तरीके से ट्रांसपोंडर के उपयोग का लाइसेंस देना। इसका मतलब यह है कि जैसा कि शिकायत में कहा गया है, शिकायतकर्ता ने स्वयं आरोपी नंबर 4 और 5 के माध्यम से आरोपी नंबर 1 के साथ बातचीत का उल्लंघन किया था। जारी किए गए शेयर पूंजी के 100% के हस्तांतरण के लिए @ रु. सितंबर/अक्टूबर, 1988 के महीने में शिकायतकर्ता नंबर 1 द्वारा रखे गए शिकायतकर्ता नंबर 2 के प्रति शेयर 7.40, उनसे संपर्क करने पर शिकायतकर्ताओं ने स्वीकार किया कि पार्टियों के बीच विभिन्न चर्चाएं हुईं और यह संयुक्त के बाद ही हुआ है उपर्युक्त आरोपी की ओर से शिकायतकर्ताओं के प्रतिनिधि को आश्वासन दिया गया था कि यह सहमति हुई थी कि आरोपी शिकायतकर्ता नंबर 1 द्वारा रखे गए शिकायतकर्ता नंबर 2 के इक्विटी शेयर खरीदेगा। इसके बाद 2 दिसंबर, 1998 को यह एक औपचारिक दस्तावेज, उनके और आरोपी नंबर 5 के बीच निष्पादित किया गया, आरोपी नंबर 1 और 4 कंपनियों के लिए, जिसे समझौते के बिंदु के रूप में माना गया था। शिकायतकर्ताओं के रुख के अनुसार, अधिग्रहण की समय

सीमा 115 दिनों के भीतर पूरी की जानी थी। शिकायतकर्ता-कंपनी को आरोपी नंबर 1 द्वारा 30 अप्रैल, 1999 को लिया जाना था। भुगतान का तरीका भी दस्तावेज़ में निर्दिष्ट किया गया था शिकायतकर्ता के शेयरों के अधिग्रहण के तौर-तरीके तय कर लिए गए। इस दस्तावेज़ के तहत लाइसेंस प्राप्त ट्रांसपोंडर में शिकायतकर्ता का कोई भी अधिकार समझौते की तिथि पर तथ्यात्मक रूप से हस्तांतरित नहीं किया गया था। अभियुक्तों द्वारा आपराधिक साजिश के आधार पर प्राप्त किए गए इस दस्तावेज़ को उनकी ओर से गलत बयानी करार देना बिना किसी आधार के प्रतीत होता है। 2 दिसंबर, 1998 के समझौते में कोई शर्त नहीं थी कि शिकायतकर्ता अभियुक्त को ट्रांसपोंडर स्पा के उपयोग की अनुमति देगा। मई, 1999. बल्कि, वहां निर्दिष्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संभाले जाने वाले परिश्रम का विशेष संदर्भ दिया गया था और संसाधनों और तकनीकी नेटवर्क का साझाकरण टर्म शीट पर हस्ताक्षर करने और उसके बाद अभियुक्त नंबर 1 के नामांकित व्यक्ति पर होना था। शिकायतकर्ता को बोर्ड बैठक में भाग लेने की आवश्यकता थी। शिकायतकर्ता का यह मामला नहीं है कि आरोपी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर किसी भी टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए गए थे। बल्कि, शिकायतकर्ताओं का निश्चित मामला यह है कि नवंबर 1999 तक अभियुक्तों ने यह कहा था कि उनके द्वारा कोई औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई हैं, जबकि शिकायतकर्ताओं द्वारा तथ्यात्मक स्थिति पर विवाद नहीं किया गया था, हालांकि अभियुक्तों की निष्क्रियता को उनकी ओर से धोखा देने का कार्य कहा गया था। आरोपी ने जानबूझकर शिकायतकर्ताओं पर यह प्रभाव डालने के लिए ऐसा किया था कि वे अपना काम पूरा कर लेंगे। आरोपी की ओर से यह देरी शिकायतकर्ताओं को धोखा देने के लिए की गई थी। ऊपर बताए गए तथ्य उत्तरदाताओं को स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि आरोपी ने समझौते की शर्तों में बताए गए 115 दिनों के भीतर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं की थीं, फिर भी उसने नवंबर 1999 में आरोपी से संपर्क किया, जब शिकायतकर्ता को दूरसंचार विभाग को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता थी और आरोपी से पूछा गया कि नहीं। 1 ने शिकायतकर्ताओं द्वारा की गई मांगों का भुगतान करने के लिए शिकायतकर्ता को 15 नवंबर, 1999 को एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया था और इसके बाद उस दिन आरोपी नंबर 1 और शिकायतकर्ताओं के बीच एम पर हस्ताक्षर किए गए। इस दस्तावेज़ पर टेल्स्ट्रा या इसके डायरेक्टो द्वारा 15 नवंबर, 1999 के एमओयू में हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, आरपीजी टेलीफोन्स लिमिटेड का संक्षेप में "आरपीजी" और आरपीजी सैटेलाइट कम्युनिकैट लिमिटेड को "कंपनी" के रूप में वर्णित किया गया है और टेल्स्ट्रा विशेष कम्युनिकेशन लिमिटेड को "वी-कॉम" के रूप में वर्णित किया गया है।

(26) एमओयू की शर्तों को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि पार्टियों ने खंड 2 में संदर्भित प्रस्तावित लेनदेन पर बातचीत करने का इरादा किया था। खंड 2 के तहत, आरपीजी द्वारा वी-कॉम को बिक्री और हस्तांतरण से संबंधित लेनदेन। कंपनी के जारी किए गए शेयरों का 100% हिस्सा बनता है। पार्टियों के बीच इस बात पर भी सहमति हुई कि ऐसे किसी भी शेयर को खरीदने का वी.कॉम का दायित्व ऐसे सभी शेयरों की खरीद पर निर्भर होगा। शेयरों का खरीद मूल्य 70 मिलियन रुपये होने की उम्मीद थी। 5 प्रति शेयर जैसा कि समझौते के खंड 4 में बताया गया है। क्लॉज 4 के तहत ए2 आरपीजी को एमओयू के निष्पादन के 7 दिनों के भीतर वी-कॉम को अपनी संतुष्टि प्रदर्शित करनी थी कि रु. कंपनी की ओर से आरपीजी द्वारा डीओटी को 14,61,695.00 रुपये के दंड ब्याज के साथ 10,55,000 रुपये का भुगतान किया गया है। इस समझौते में आगे उल्लेख किया गया था कि कंपनी नेटवर्क सेवा समझौते को निष्पादित करेगी और यदि यह 7 दिनों के भीतर किया जाता है तो वी-कॉम। कंपनी की ओर से डीओटी को तुरंत रुपये का भुगतान करना होगा। 1,22,59,603.00 जिसमें लाइसेंस शुल्क रु. शामिल है। 31,67,603.00 और अंतरिक्ष खंड शुल्क रु। 90,92,000.00 जो कंपनी द्वारा डीओटी को देय था। खंड 4.ए के तहत, यह प्रावधान किया गया था कि रुपये की राशि। जुलाई 1999 की अवधि के लिए कंपनी द्वारा डीओटी को देय राशि से संबंधित भुगतान के हिस्से के रूप में 25,88,581.00 रुपये को शेयर खरीद समझौते के तहत एक जमा माना जाएगा और 96,71,022.00 रुपये की कुल राशि का आंशिक भुगतान हिस्सा होगा। भुगतान वी कॉम द्वारा ऋण बनता है। कंपनी को 1 जुलाई, 1999 से पहले की अवधि के लिए शेयर खरीद समझौते के निष्पादन की तारीख तक डीओटी के प्रति अपने कुछ दायित्वों को पूरा करने के लिए (दंड ब्याज के संबंध में नहीं)। जैसा कि खंड 5.1 (सी) में कहा गया है, संतोषजनक उचित परिश्रम के संबंध में आरपीजी और कंपनी ने प्रथागत संचालन की अनुमति दी थी और इस तरह के उचित परिश्रम को वी-कॉम की संतुष्टि के लिए पूरा किया जाना था, इस समझौते के तहत लेन-देन का समापन किया जाना था। 28 फरवरी, 2000 को या उससे पहले होने का इरादा है। खरीद समझौते की शर्तें खंड 5.2 में निर्दिष्ट की गई थीं। वी-कॉम पर डाले गए दायित्व का उल्लेख करना उचित होगा। समझौते के खंड 6 के तहत जो इस प्रकार है:-

"डुए डिलिजेंस :-

6.1 कंपनी वी-कॉम की अनुमति देगी। और वी-कॉम के वित्तीय कानूनी और अन्य सलाहकार। बाहर ले जाने के लिए कंपनी की तकनीकी, वित्तीय और कानूनी उचित परिश्रम जांच, उसके परिणाम और उसके संचालन, जिसमें लाइसेंस, अनुबंध, पुस्तकों और रिकॉर्ड, भौतिक संयंत्र, संचालन के परिणाम और कर मामलों की बिना किसी सीमा के जांच और परिसंपत्तियों के मूल्य का सत्यापन शामिल है। 30 जून, 1999 और 30 सितंबर, 1999 को कंपनी की देनदारियां और तिथि के अनुसार Vsats के स्थापित आधार पर राजस्व धाराएं।

6.2 कंपनी वी-कॉम को उपलब्ध कराएगी। सलाहकार ऐसे रिकॉर्ड और सामग्री, कंपनी के ऐसे वरिष्ठ और अन्य कर्मियों, इसके बाहरी लेखा परीक्षकों और इसके बाहरी कानूनी सलाहकारों को चर्चा के लिए उपलब्ध कराते हैं, और कंपनी के भौतिक संयंत्र को सुलभ बनाते हैं, जैसा कि उनमें से कोई भी उचित रूप से अनुरोध कर सकता है।

6.3. वी-कॉम. 31 जनवरी 2000 तक अपना उचित परिश्रम कार्य पूरा करने का प्रयास करेगा।

6.4. उचित परिश्रम पूरा होने के 14 दिनों के भीतर, वी-कॉम। नोटिस द्वारा आरपीजी को सलाह दी जाएगी कि वह प्रस्तावित लेनदेन के साथ आगे बढ़ने का इरादा रखता है या नहीं। यदि वी-कॉम. लेन-देन को आगे बढ़ाने का इरादा रखता है तो उसे उस नोटिस में शेयरों के लिए अपेक्षित खरीद मूल्य की पुष्टि या संशोधन करना होगा। यदि वी-कॉम. आरपीजी को सूचित करता है कि वह आगे नहीं बढ़ना चाहता है तो यह समझौता ज्ञापन समाप्त हो जाएगा, बशर्ते कि यह खंड 6 खंड 4ए के साथ हो। 9, 10.1(ई), 11, 12,14 और 15 समाप्ति से बचे रहेंगे।

6.5 यदि वी-कॉम. शेयरों के लिए संशोधित खरीद मूल्य के बारे में आरपीजी को सूचित करता है और आरपीजी उस संशोधित मूल्य को स्वीकार नहीं करता है और वी-कमांड आरपीजी 15 दिनों के भीतर संशोधित मूल्य पर समझौते तक पहुंचने में विफल रहता है, फिर वी-कॉम। या आरपीजी दूसरे को नोटिस देकर इस एमओयू को समाप्त कर सकता है, बशर्ते कि यह खंड 6, खंड 4ए, 9, 10.1(ई), 11,12, 14 और 15 के साथ समाप्ति से बचा रहेगा।

6.6. वी-कॉम. वी-कॉम को बताई गई गोपनीय जानकारी को गोपनीय रखने का वचन देता है। उचित परिश्रम के भाग के रूप में।

6.7. खंड 6.6 में कुछ भी वी-कॉम को रोकता नहीं है। कंपनी और वी-कॉम के बीच निष्पादित मौजूदा गोपनीयता समझौते के अनुपालन के अधीन अपने सलाहकारों, शेयरधारकों और उनके कर्मचारियों और सलाहकारों को किसी भी गोपनीय जानकारी का खुलासा करना।" खंड 7 और 15 आगे निम्नानुसार प्रदान करते हैं: -

"7. कर्मचारी:

7.1. वी-कॉम कंपनी के कर्मचारियों की सूची। बनाए रखने की इच्छा अनुबंध 2 में संलग्न है। शेयरों की किसी भी बिक्री के पूरा होने तक: (i) कंपनी शेयरों की किसी भी बिक्री के पूरा होने तक इन व्यक्तियों को अपने रोजगार में बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगी; (ii) शेयरधारक यह सुनिश्चित करेंगे कि कंपनी वी-कॉम को स्वीकार्य शर्तों पर अपने अन्य कर्मचारियों को बर्खास्त कर दे। और शेयरधारक कंपनी वी-कॉम को क्षतिपूर्ति देंगे और क्षतिपूर्ति करते रहेंगे। ऐसे कर्मचारियों द्वारा किए जा सकने वाले सभी दावों के विरुद्ध।

XX XX XX XX XX XX

15. कोई बाध्यकारी बाध्यता नहीं:

15.1. खंड 3, 4ए, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 15 के प्रावधानों को छोड़कर, यह एमओयू किसी भी कानूनी बाध्यकारी या लागू करने योग्य दायित्व का गठन या निर्माण नहीं करता है, और इसे गठित या निर्मित करने वाला नहीं माना जाएगा। किसी भी पार्टी का. खंड 5 में निर्दिष्ट समझौतों के निष्पादन और वितरण को छोड़कर, ऐसी कोई बाध्यता नहीं बनाई जाएगी, जिसमें पार्टियों द्वारा सहमत लेनदेन के ऐसे नियम और शर्तें शामिल हैं, और उसके बाद केवल नियमों और शर्तों के अनुसार। ऐसे समझौते।"

(27) 15 नवंबर 1999 को पार्टियों के बीच निष्पादित नेटवर्क सेवा समझौते से यह स्पष्ट है कि पार्टियों ने विशेष रूप से 1ए.1 के रूप में पूर्ववर्ती शर्तों का संकेत दिया है, जिसके तहत पार्टियों

के बीच किए गए सभी पूर्व अनुबंध, व्यवस्थाएं और समझ नेटवर्क की व्यवस्था के संबंध में सेवाएँ (जैसा कि खंड 1 बी में परिभाषित है) प्रारंभ तिथि पर समाप्त हो जाएंगी। इस समझौते के खंड 2.1, 2.2, 3.1 और 3.2 निम्नलिखित शर्तों में हैं:

"2. विचार

2.1. खंड 22, वी-कॉम के प्रावधानों के अधीन। इस समझौते की अवधि के लिए आरपीजी को प्रति माह 0.85 मिलियन रुपये ("मासिक भुगतान") का भुगतान करना होगा। मासिक भुगतान अग्रिम रूप से देय है।

2.2 पूर्व अनुबंधों के अनुसार, वी-कॉम। रुपये का भुगतान किया 3.03 मिलियन जिसमें से आरपीजी स्वीकार करता है कि रु। 0.5.11 मिलियन ("बकाया राशि") अब आरपीजी द्वारा वी-कॉम को वापस किया जा सकता है। (इस समझौते के अनुसार पूर्व अनुबंधों की शीघ्र समाप्ति के कारण)। इसके अलावा और क्लॉज

3.1 में परिभाषित एमओयू 9 की शर्तों के अधीन), वी-कॉम। दूरसंचार विभाग ("डीओटी") को रुपये का भुगतान करेगा। 1,22,39,603.00 जो राशि भुगतान पर होगी (एमओयू की शर्तों के अनुसार उस राशि ("जमा") के लिए एक जमा राशि का गठन किया जाएगा। वी-कॉम के विकल्प पर जमा और बकाया राशि को मासिक के विरुद्ध सेट किया जा सकता है भुगतान प्रारंभ तिथि से वी-कॉम द्वारा भुगतान किया जाना है। बशर्ते कि यदि वी-कॉम इस विकल्प का उपयोग करता है तो पार्टियां स्वीकार करती हैं कि बकाया राशि को पहले मुजरा माना जाएगा और जमा केवल बकाया होने पर ही मुजरा किया जाएगा। राशि पूरी तरह से सेट कर दी गई है।

Xx xx xx xx

3. अवधि और समाप्ति

3.1 यह समझौता तब तक लागू रहेगा जब तक कि किसी शेयर खरीद समझौते के तहत पूरा नहीं हो जाता (जैसा कि एमओयू द्वारा विचार किया गया है) या बकाया राशि और जमा को खंड

2 के अनुसार मासिक भुगतान से पूरी तरह से अलग कर दिया गया है, जब तक कि इसकी शर्तें अनुसार जल्द ही समाप्त न हो जाए।

3.2 वी-कॉम. इस अनुबंध को किसी भी समय 2 दिन के नोटिस पर कारण सहित या बिना कारण समाप्त कर सकता है। ऐसी समाप्ति पर, आरपीजी तुरंत वी-कॉम को वापस कर देगा। का कुल:

(ए) जमा और बकाया राशि में से किसी भी मासिक भुगतान को घटाकर जो कि खंड 2.2 के अनुसार जमा और बकाया राशि से काटा गया है; और

(बी) उन महीनों के लिए मासिक भुगतान जिनमें नेटवर्क सेवाएं वी-कॉम की संतुष्टि के अनुसार निष्पादित नहीं की गई हैं।"

एक अन्य समझौता जिसका शिकायत और सम्मन आदेश में कोई संदर्भ नहीं दिया गया था, वह आरपीजी, कंपनी और वी-कॉम के बीच निष्पादित कॉर्पोरेट गारंटी है। इस गारंटी का कारण स्पष्ट रूप से निम्नानुसार बताया गया है-

"1. आरपीजी और वी-कॉम ने कंपनी के संबंध में कुछ लेन-देन के संबंध में 15 नवंबर, 1999 को एक समझौता ज्ञापन और नेटवर्क सेवा समझौता किया है, जो आरपीजी, वी-कॉम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। आरपीजी के अनुरोध पर, 1,22,59,603.00 रुपये (कंपनी की ओर से दूरसंचार विभाग को देय "राशि") का भुगतान करने पर सहमत हुआ है।

2. वी-कॉम पर विचार. ऐसा भुगतान करने पर, आरपीजी, वी-कॉम द्वारा भुगतान की गई सभी राशियों की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी देने पर सहमत हो गया है। कंपनी के लिए डीओटी को

(28) उपरोक्त दस्तावेजों की शर्तों के विस्तृत संदर्भ की आवश्यकता उत्पन्न हुई है क्योंकि तर्क के दौरान, उत्तरदाताओं-शिकायतकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने आग्रह किया कि समझौते के बिंदुओं के निष्पादन के बाद के दस्तावेज़ किसी भी तरह से भिन्न नहीं थे और समझौते के बिंदुओं में पार्टियों के बीच सहमत शर्तों को प्रतिस्थापित करें। रिकॉर्ड के तौर पर यह प्रस्तुति

ऊपर उल्लिखित विभिन्न कथनों द्वारा समर्थित नहीं है। समझौता ज्ञापन, नेटवर्क सेवा समझौता और कॉर्पोरेट गारंटी। ऊपर उल्लिखित एमओयू के खंड 5 में बिना किसी अनिश्चित शर्तों के प्रावधान किया गया है कि अधिग्रहण के लिए शर्त, मिसाल यह है कि अधिग्रहण के लिए शर्त, मिसाल आरोपी नंबर 1 की संतुष्टि के लिए उचित परिश्रम पूरा करना था। यही कारण है एमओयू के खंड 5.2 में यह कहा गया है कि कोई भी खरीद समझौता स्वयं विभिन्न पूर्ववर्ती शर्तों की संतुष्टि के अधीन होगा, जिसमें आरोपी नंबर 1 के बोर्ड और शेयर धारकों के साथ-साथ टेल्स्ट्रा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड की मंजूरी भी शामिल होगी। एमओयू का खंड 1.5 आगे यह प्रावधान करता है कि खंड 3, 4ए, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 15 के प्रावधानों को छोड़कर, एमओयू की अन्य शर्तें किसी का गठन या निर्माण नहीं करती हैं और न ही उन्हें गठित या निर्मित माना जाएगा। किसी भी पक्ष पर कानूनी रूप से बाध्यकारी या लागू करने योग्य दायित्व। इसलिए, एमओयू की शर्तों के अनुसार, पार्टियों ने नेटवर्क सेवा समझौते में निर्दिष्ट प्रस्तावित लेनदेन के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया था। यहां तक कि नेटवर्क सेवा समझौते में भी, यह विशेष रूप से कहा गया था कि "ऐसे एनएसए के प्रावधानों के संबंध में पार्टियों के बीच किए गए सभी पूर्व अनुबंध, व्यवस्थाएं और समझ शुरुआत के दिन समाप्त हो जाती हैं," ट्रांसपोंडर तक पहुंच सहित कुछ सेवाओं के पूरा होने पर आरोपी नंबर 2 के गठित प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस समझौते के तहत कर्मचारियों के रोजगार और शिकायतकर्ताओं के नेटवर्क के विस्तार पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए, आरोपी नंबर 1 रुपये का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ था। शिकायतकर्ता नंबर 1 को 0.585 मिलियन प्रति माह। आरोपी नंबर 1 ने आरोपी नंबर 1 की ओर से डीओटी को 25,88,581 रुपये का भुगतान करने पर भी सहमति व्यक्त की थी, जिसे मासिक भुगतान के खिलाफ जमा राशि के रूप में गठित किया जाना था। शिकायतकर्ताओं ने याचिकाकर्ताओं को शिकायतकर्ता नंबर 2 के स्वामित्व वाली राशि रुपये तक का भुगतान करने के लिए आरोपी नंबर 1 के पक्ष में एक कॉर्पोरेट गारंटी निष्पादित करके स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की थी। 1,22,59,603. अभियुक्तों का यह निश्चित मामला है कि उचित परिश्रम पूरा नहीं किया गया था और अभियुक्तों की ओर से किए गए अनुरोध पर शिकायतकर्ताओं द्वारा स्वयं मार्च 2000 तक अवधि बढ़ा दी गई थी, जैसा कि रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों से स्पष्ट रूप से बताया गया है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि मार्च 2000 में शिकायतकर्ता नंबर 2 को डीओटी शुल्क के रूप में रुपये का भुगतान करना पड़ा। 140.13 लाख. भुगतान करने के बजाय, शिकायतकर्ता नंबर 2 ने आरोपियों से इस दलील पर उक्त भुगतान की व्यवस्था करने के लिए कहा कि वे ट्रांसपोंडर स्पेस की संपूर्ण सेवाओं का उपयोग करना, जिस प्रतिबद्धता पर

आरोपी सहमत नहीं था क्योंकि अधिग्रहण का निर्णय तब तक आरोपी नंबर 1 के निदेशक मंडल द्वारा नहीं लिया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है, आरोपी नंबर 1 ने शिकायतकर्ताओं को सूचित किया था अप्रैल 2000 में कहा गया कि उन्हें उनका सहयोग करना चाहिए। शिकायतकर्ताओं को यह भी सूचित किया गया कि उन्हें टेल्स्ट्रा वी-कॉम प्रदान करना जारी रखना चाहिए। 'नेटवर्क सेवा समझौता तब तक होगा जब तक कि नाममात्र सेवा शुल्क रुपये की राशि के विरुद्ध पूरी तरह से समायोजित नहीं हो जाता। शिकायतकर्ताओं की ओर से आरोपी नंबर 1 द्वारा डीओटी को 1,22,59,603 रुपये का भुगतान किया गया। मामला अगस्त 2000 तक चलता रहा जब रुपये की और मांग की गई। शिकायतकर्ताओं द्वारा आरोपी नंबर 1 से ट्रांसपोंडर शुल्क और लाइसेंस शुल्क के लिए उस अवधि के लिए 2,43,53,046 रुपये का भुगतान किया गया जब आरोपी नंबर 1 ट्रांसपोंडर सुविधा का उपयोग कर रहा था। आरोपियों ने जवाब में बताया कि रुपये की मांग की गयी है. शिकायतकर्ताओं को ट्रांसपोंडर की लागत और लाइसेंस शुल्क के लिए 2,43,53,046 रुपये का भुगतान करना पड़ा। नेटवर्क सेवा समझौते सहित ऊपर उल्लिखित किसी भी समझौते में ऐसा कोई खंड नहीं बताया जा सकता है, जिसके तहत यह कहा जा सके कि आरोपी डीओटी के प्रति शिकायतकर्ताओं से ट्रांसपोंडर स्पेस और लाइसेंस शुल्क का दायित्व लेने के लिए सहमत हुआ था। वास्तव में, रिकॉर्ड पर प्रस्तुत दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि ऐसा कोई दस्तावेज़ अस्तित्व में नहीं आया है जिसके द्वारा आरोपी ने शिकायतकर्ताओं की कंपनी पर कब्जा कर लिया था और यही कारण है कि शिकायतकर्ताओं ने अपनी इच्छा से 26 नवंबर को टेलीग्राम द्वारा पार्टियों के बीच समझौते को समाप्त कर दिया। 2000 (परिशिष्ट-पृ. 10)।

(29) दस्तावेजों और रिकॉर्ड पर पेश किए गए सबूतों से, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि शिकायतकर्ताओं की ओर से आरोपियों को जो भी सुविधा दी गई थी, वह अंतरिम के रूप में पार्टियों के बीच सहमत नेटवर्क सेवा समझौते के संदर्भ में विचार के लिए थी। शिकायतकर्ताओं की ओर से बनाए गए हेराफेरी और धोखाधड़ी के उपाय और प्रश्न रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री द्वारा समर्थित नहीं हैं। बल्कि, शिकायतकर्ताओं ने स्वयं कॉर्पोरेट गारंटी में प्रवेश किया था जो शिकायतकर्ताओं की ओर से उठाए गए रुख को पूरी तरह से रद्द कर देता है। प्रथम दृष्टया यह नहीं पाया गया कि आरोपी ने शिकायतकर्ताओं को बेईमानी और कपटपूर्ण इरादे से शिकायतकर्ताओं के साथ समझौता करने के लिए प्रेरित किया था। यह स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड पर लाया गया है कि नागरिक विवाद की मांग की गई है। शिकायतकर्ताओं को आपराधिकता का

रंग दिया जाए ताकि उन पर आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 406, 420 और 120-बी के तहत मुकदमा चलाया जा सके। शिकायत दर्ज करना और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन आदेश रिकॉर्ड के तौर पर अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

(30) नतीजतन, मैं याचिकाएं स्वीकार करता हूं और शिकायत और याचिकाकर्ता-अभियुक्तों के खिलाफ पारित 22 मई, 2001 के समन आदेश को रद्द करता हूं।

*****

<u>अस्वीकरण</u>: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है, ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मीनू वर्मा,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा